

## वृद्ध आर्थिक रूपरेखा विवरण

### अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था में 2011-12 के 6.2 प्रतिशत के विकास के पश्चात् 2012-13 में उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से 2004-05 की स्थिर कीमतों पर 5.0 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की गई है। 2003-04 से 2012-13 तक के दशक के दौरान 7-9 प्रतिशत की औसत के संदर्भ में 2011-12 और 2012-13 में विकास कम रहा। इसकी मुख्य वजह 2011-12 के अधिकांश भाग के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई सख्त मौद्रिक नीति के संदर्भ में कमजोर औद्योगिक विकास तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सतत अनिश्चितता रही। शीर्ष थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति में कुछ गिरावट के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अप्रैल 2012 में रेपो दर में 50 आधार बिन्दुओं और जनवरी 2013 में 29 आधार बिन्दुओं की कमी की गई। सख्त मौद्रिक नीति का प्रभाव सकल घरेलू उत्पाद की तिमाही वृद्धि दर में देखा गया है। सकल घरेलू उत्पाद की तिमाही वृद्धि में 2010-11 की चौथी तिमाही और 2011-12 की चौथी तिमाही के बीच की प्रत्येक क्रमिक तिमाहियों में गिरावट रही। अर्थव्यवस्था, विशेषकर उद्योग क्षेत्र में मंदी से सरकारी राजस्व में बजटीय वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि रही। तथापि, मध्यावधिक सुधार के भाग के रूप में किए गए उपायों से 2012-13 के व्यय परिणाम में सुधार करने हेतु सहायता मिली है। तेल विपणन कम्पनियों को डीजल की कीमतों में नियमित रूप से अल्प बढ़ोतरी की अनुमति देकर डीजल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने सहित कई उपायों और सब्सिडीकृत एलपीजी सिलिंडरों की संख्या पर उच्चतम सीमा से राजकोषीय घाटे पर रोक लगाए जाने की प्रत्याशा है। चालू वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान निर्यात में गिरावट और हाल के महीनों में आयात में वृद्धि से अप्रैल-दिसम्बर 2012 के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 147 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2012-13 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत पर चालू खाता घाटा चिंता का कारण है। अगस्त 2011 से व्यापार और चालू खाता घाटों में बढ़ोतरी के साथ रुपए के मूल्य में गिरावट रही। 27 जून, 2012 को रुपए का मूल्य 57.22 रुपए प्रति अमरीकी डालर के सर्वकालिक निम्न स्तर से उठकर जनवरी 2013 में 53-55 रुपए प्रति अमरीकी डालर के रेंज में आ गया। 2010-11 और 2011-12 के दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में निरंतर उच्च स्तर रहने के पश्चात् दिसम्बर 2011 से गिरावट के संकेत दिखाई पड़े हैं। तथापि, विगत 12 माह मुद्रास्फीति लगभग 7 से 8 प्रतिशत के बीच स्थिर रही। हाल के महीनों में व्यापक सुधार उपायों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2013-14 में मामूली वापसी के साथ संभलने से भारतीय अर्थव्यवस्था में 2013-14 के दौरान वर्धित संभावना देखे जाने की प्रत्याशा है।

### सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी अग्रिम अग्रिमों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 2012-13 के दौरान उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से 2011-12 के 6.2 प्रतिशत और 2010-11 के 9.3 प्रतिशत के मुकाबले 5.0 प्रतिशत विकास दर दर्ज होने का अनुमान है। यह विकास दर न केवल हाल के समय की तुलना में बल्कि 2003-04 से देखी गई विकास प्रवृत्तियों के संदर्भ में भी निम्न स्तर पर रही। 2012-13 के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास में मंदी मुख्यतया औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के कारण रही। 2012-13 में औद्योगिक क्षेत्र के 2011-12 के 3.5 प्रतिशत के मुकाबले 3.1 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र के 2011-12 के 3.6 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले 1.8 प्रतिशत की कम विकास दर पर विकसित होने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र में 2012-13 के दौरान 6.6 प्रतिशत की दर पर विकास होने का अनुमान है, जो 2011-12 की विकास दर के मुकाबले निम्न है। 2011-12 और 2012-13 में मंदी घरेलू कारकों के साथ-साथ शेष विश्व विशेषकर विकसित अर्थव्यवस्था और भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों से उत्पन्न होने वाले कारकों की वजह से हुई है। यूरो जोन क्षेत्र में संकट और कई अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में धीमे विकास से भारत में परिवर्तनात्मक संयोजनों के जरिए विकास प्रभावित हुआ है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने और स्फीतिकारी प्रत्याशाओं में रोक लगाने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति को सख्त करने सहित घरेलू कारकों के परिणामस्वरूप विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में निवेश और विकास में मंदी आई।

सीएसओ द्वारा जारी तिमाही आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के विकास की दर 5.3 प्रतिशत थी। 2008-09 की चौथी तिमाही से विकास निम्नतम रहा है। 2012-13 की दूसरी तिमाही में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की विकास दर 2011-12 की तदनुसूची तिमाही की क्रमशः 3.1 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत और 8.8 प्रतिशत के मुकाबले क्रमशः 1.2 प्रतिशत, 2.8 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों में संचयी विकास दर विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि के 7.3 प्रतिशत के मुकाबले 5.4 प्रतिशत (दोनों तिमाहियों को मिलाकर) रही।

अनुमान की व्यय पद्धति की दृष्टि से स्थिर बाजार मूल्यों पर 2012-13 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 2011-12 के 6.3 प्रतिशत के मुकाबले 3.3 प्रतिशत दर्ज होने का अनुमान है। विकास में इस मंदी के तीन प्रमुख घटक नामतः खपत व्यय, सकल नियत पूंजी निर्माण और निर्यात में वृद्धि है, जो 2012-13

के दौरान वास्तविक दृष्टि से गिरकर क्रमशः 4.1 प्रतिशत, 2.5 प्रतिशत और 5.1 प्रतिशत हो गई। 2011-12 में इन घटकों में क्रमशः 8.1 प्रतिशत, 4.4 प्रतिशत और 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अर्थव्यवस्था में 2011-12 के दौरान निवेश की वृद्धि में 2010-11 की तुलना में काफी गिरावट दर्ज हुई। इसकी वजह से 2010-11 और अधिकांशतः 2011-12 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई सख्त मौद्रिक नीति रही जिसके फलस्वरूप उधारों की उच्च लागत और घरेलू व विदेशी मांग में मंदी आई। सीएसओ द्वारा जारी पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू बाजार मूल्यों (बचत दर) पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचत 2010-11 के 34.0 प्रतिशत से गिरकर 2011-12 में 30.8 प्रतिशत हो गई। यह गिरावट मुख्यतया सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों में कमी और परिवारों द्वारा वित्तीय बचतों में कमी आने की वजह से हुई।

### कृषि उत्पादन

कृषि उत्पादन अधिकांशतः दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा द्वारा प्रभावित क्षेत्र बना रहा। सामान्य वर्ष के साथ 2011-12 में कृषि ने रिकार्ड उत्पादन दर्ज कराया था। 2012 के दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान दीर्घ आवधिक औसत (एलपीए) की तुलना में देश में समग्रतः 8 प्रतिशत वर्षा हुई। कृषि तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में विकास से संबंधित राष्ट्रीय लेखा आंकड़े वर्ष 2010-11 में 7.9 प्रतिशत थे तथा 2011-12 में इनके 3.6 तथा 2012-13 में 1.8 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) होना अनुमानित है। चावल तथा गेहूं उत्पादन द्वारा चालित खाद्य उत्पादन 2010-11 में 244.49 मिलियन टन के मुकाबले 2011-12 में 259.32 मिलियन टन के ऑल टाइम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2012-13 के जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार चावल का उत्पादन 101.80 मिलियन टन, गेहूं 92.30 मिलियन टन, तथा कपास के 170 कि.ग्रा. प्रत्येक की 33.80 मिलियन गांठों के उत्पादन का अनुमान है। 2012-13 में दलहन का उत्पादन 17.58 मिलियन टन, गन्ने का 334.54 मिलियन टन तथा तिलहन का 294.65 लाख टन होना अनुमानित है। इस वर्ष खरीफ में बारिश की कमी के चलते 2011-12 की तुलना में 2012-13 में दलहन के अलावा ज्यादातर प्रमुख फसलों के उत्पादन में कमी का अंदेशा है।

कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में विकास ग्यारहवीं योजना लक्ष्यों से कम हुआ है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि ग्यारहवीं योजना में 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 3.6 प्रतिशत रही है। कवरेज क्षेत्र में दी गई स्पष्ट सीमा दीर्घ आवधिक वृद्धि मुख्यतः फसलों की पैदावार पर निर्भर रही है। इसे वृद्धिपरक उत्पादकता अर्जनों तथा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रसार के द्वारा हासिल किया जाता है। इसको प्रभावित करने वाला एक अहम कारक कृषि में अनुप्रयुक्त सकल पूंजी निर्माण का स्तर है। कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धित सकल पूंजी निर्माण का अनुपात (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर) 2011-12 में 19.8 प्रतिशत था जबकि 2007-08

में यह 16.1 प्रतिशत था। तथापि, अर्थव्यवस्था के समग्र सकल पूंजी निर्माण में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की हिस्सेदारी मिली-जुली रही है। सरकार कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में वास्तविक ऋण इस संबंध में नियत लक्ष्य को भी पार कर चुके हैं। 2012-13 में 575000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक ऋण सितम्बर 2012 तक 239629 करोड़ रुपए था।

### कीमते

मुख्य मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ में मापी जाती है। 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) में औसतन 7.55 प्रतिशत थी। जबकि 2011-12 में समान अवधि के दौरान यह 9.44 प्रतिशत रही थी। 2012-13 का वित्तीय वर्ष 7.50 प्रतिशत की हेडलाइन मुद्रास्फीति के साथ आरंभ हुआ था। पिछले बारह महीनों में मुद्रास्फीति 7-8 के दरम्यान बनी रही।

समग्र थोक मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति में 24.31 प्रतिशत अधिभार सहित प्राथमिक रूप से खाद्य वस्तुएं तथा विनिर्मित खाद्य उत्पाद शामिल होते हैं। 2011-12 में तदनुसूची अवधि के दौरान 7.91 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में यह औसतन 9.08 प्रतिशत रहा। दिसम्बर 2011 के दौरान 2.70 प्रतिशत की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति 10.39 प्रतिशत थी।

पशु उत्पादों (अंडा, मांस तथा मछली) का सतत उच्च मूल्य, अनाजों तथा सब्जियों के मूल्य में वृद्धि, साथ ही में उर्वरकों (गैर-यूरिया) के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और डीजल के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि से मुद्रास्फीति में समय-समय पर अलग-अलग स्तर देखा गया है।

मुख्य सूचकांकों की उपभोक्ता मूल्य मुद्रा-स्फीति में सामान्यतः एक जैसी प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) में सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रा-स्फीति की औसत पूर्व वर्ष की समान अवधि के दौरान 8.82 प्रतिशत की तुलना में 10.0 प्रतिशत रही। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने जनवरी 2011 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की एक नई श्रृंखला शुरू की। सीपीआई-एनएस के लिए अखिल भारतीय सामान्य मुद्रास्फीति का औसत वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर) में 10.04 प्रतिशत रहा और दिसम्बर 2012 में 10.56 प्रतिशत रहा। अन्य समूह विशिष्ट सीपीआई (कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई तथा ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति भी दिसम्बर 2012 में दो अंकों में बनी रही। जहां उच्च सीपीआई मुद्रास्फीति का एक भाग खपत समूह में (46-69 प्रतिशत) में खाद्य का उच्च भार दर्शाता है वहीं सेवाओं और आवास के क्षेत्रों, जिन्हें सीपीआई समूह में शामिल किया गया है, में मूल्य संबंधी दबाव बना हुआ है।

### उद्योग और सेवाएं

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) आधार के रूप में 2004-05 के साथ औद्योगिक निष्पादन का अग्रणी सूचक

है। आईआईपी के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर 2012 के दौरान, पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 3.7 प्रतिशत की तुलना में, औद्योगिक निष्पादन वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत थी। वर्तमान वर्ष के दौरान वैश्विक तथा घरेलू दोनों कारकों से औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है। वर्तमान वर्ष में संकुचन मुख्यतः पूंजीगत माल, प्राकृतिक गैस, कच्चे पेट्रोलियम तथा उर्वरकों के उत्पादन में कमी के कारण था। संपूर्ण औद्योगिक निष्पादन, जैसाकि आईआईपी द्वारा दर्शाया गया है, में 2011-12 की पहली तिमाही से गिरावट जारी रही और 2012-13 की पहली तिमाही में इसकी वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई तथा 2012-13 की तीसरी तिमाही में सुधरकर 2.1 प्रतिशत हो गई। विनिर्माण, जो उद्योग का प्रमुख क्षेत्र है, बिजली क्षेत्र की तरह इसकी वृद्धि में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि की 4.0 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2012 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 0.7 प्रतिशत थी। बिजली क्षेत्र की दर विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि की 9.4 प्रतिशत के मुकाबले अप्रैल-दिसम्बर 2012 के दौरान 4.6 प्रतिशत थी। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि की (-)2.6 प्रतिशत की तुलना में (-)1.9 प्रतिशत थी। अक्टूबर 2012 में समग्र आईआईपी की वृद्धि दर में तीव्र वृद्धि हुई जिससे विनिर्माण वृद्धि 9.8 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो जून 2011 से सबसे अधिक थी। तथापि, वृद्धि में दिसम्बर 2012 में (-)0.6 प्रतिशत की कमी आई। पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में निष्पादन अप्रैल-दिसम्बर 2012 के दौरान 10.1 प्रतिशत कम रहा, यह मुख्यतः मशीनरी और उपस्कर, इलेक्ट्रीकल मशीनरी तथा परिवहन खंडों में सतत ऋणात्मक वृद्धि के कारण हुआ। तथापि, वर्तमान आंकड़े यह दर्शाते हैं कि औद्योगिक विकास में गिरावट समाप्त हो सकती है।

व्यवसाय माहौल में सुधार और निवेशकों के बोध व अन्य विकासशील देशों में औद्योगिक कार्यकलापों में आंशिक उछाल के चलते आगामी वित्त वर्ष में औद्योगिक वृद्धि में सुधार की संभावना है।

### वैदेशिक क्षेत्र

भारत के निर्यात की वृद्धि दर 2010-11 में 40.5 प्रतिशत थी। यह मंद होकर 2011-12 में 21.3 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान निर्यातों का मूल्य 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में 226.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में 5.5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 214.1 बिलियन अमरीकी डालर था। इस अवधि के दौरान आयातों का मूल्य 361.3 बिलियन अमरीकी डालर था जो 2011-12 की तदनुसूची अवधि में 363.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर मामूली रूप 0.7 प्रतिशत कम था। सोने और चांदी के मूल्यों में वृद्धि के साथ बढ़ते हुए कच्चे तेल के मूल्यों ने आयात बिल में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। कुल आयातों में, पीओएल आयात अप्रैल-दिसंबर 2012 में 124.5 बिलियन अमरीकी डालर (कुल आयात का 34.5 प्रतिशत) बैठता है। यह 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में 111.0 बिलियन अमरीकी

डालर के स्तर से 12.2 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान पीओएल-भिन्न आयात 236.7 बिलियन अमरीकी डालर का था जो 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में 252.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 6.4 प्रतिशत कम था। इसके परिणामस्वरूप 2012-13 (अप्रैल-दिसंबर) का व्यापार घाटा 2011-12 (अप्रैल-दिसंबर) में 137.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़कर 147.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

हालांकि अप्रैल-दिसंबर 2012 की अवधि के पण्य व्यापार आंकड़े उपलब्ध हैं, भुगतान शेष से संबंधित अधिकतर सूचना 2012-13 के पूर्वार्ध अर्थात् अप्रैल-सितंबर के लिए ही उपलब्ध है। वर्ष 2012-13 के पूर्वार्ध में व्यापार घाटे में मामूली वृद्धि हुई जो 2011-12 के पूर्वार्ध में 89.5 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ का 9.9 प्रतिशत) की तुलना में 90.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 90.7 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ का 10.8 प्रतिशत) था। 2012-13 के पूर्वार्ध के दौरान आयातों की तुलना में निर्यातों में तीव्र गिरावट व्यापार घाटा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी थी। निवल अदृश्य शेष 2011-12 के पूर्वार्ध में 53.1 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ का 5.9 प्रतिशत) से गिरकर 2012-13 के पूर्वार्ध में 51.9 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ का 6.2 प्रतिशत) रह गए। निवल अदृश्य प्राप्तियां बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने में अपर्याप्त थीं। व्यापार घाटे के बढ़ने और निवल अदृश्य अधिशेषों में मंदी के परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा 2012-13 के पूर्वार्ध में 2011-12 की तदनुसूची अवधि में 36.4 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ का 4.0 प्रतिशत) की तुलना में और बिगड़कर 39.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

पूंजी अंतर्वाहों ने चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्ध में मिलीजुली प्रवृत्ति दर्शायी है। भारत में आगत एफडीआई 2011-12 के पूर्वार्ध में 21.9 बिलियन अमरीकी डालर से गिरकर 2012-13 के पूर्वार्ध में 16.2 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। इसी तरह, भारत द्वारा बहिर्जात एफडीआई भी अप्रैल-सितंबर 2011 में 6.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में गिरकर अप्रैल-सितंबर 2012 में 3.4 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। परिणामतः भारत को निवल एफडीआई (आगत घटा बहिर्जात) 2012-13 के पूर्वार्ध में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 15.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में गिरकर 12.8 बिलियन अमरीकी डालर रह गए। हालांकि, एफआईआई सहित निवल पोर्टफोलियो प्रवाह 2011-12 के पूर्वार्ध में 1.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में बढ़कर 2012-13 के पूर्वार्ध में 5.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। एनआरआई जमाराशियां 2012-13 के पूर्वार्ध में 9.4 बिलियन अमरीकी डालर पर सुदृढ़ बनी रही परन्तु ईसीबी के अंतर्गत निवल प्रवाह तेजी से गिरकर 2012-13 के पूर्वार्ध में 1.7 बिलियन अमरीकी डालर रह गए। निवल पूंजी प्रवाह 2011-12 के पूर्वार्ध में 43.5 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ का 4.8 प्रतिशत) की तुलना में गिरकर 2012-13 के पूर्वार्ध में 40.0 बिलियन अमरीकी डालर (सघउ का 4.8 प्रतिशत) रह गए। वर्ष 2012-13 के पूर्वार्ध में पूंजी अंतर्वाह

चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त थे और 2012-13 के पूर्वार्ध में प्रारक्षित निधि में (भुगतान शेष आधार पर) निवल संग्रहण 0.4 बिलियन अमरीकी डालर था।

वर्ष 2011-12 में विदेश मुद्रा भंडार अगस्त 2011 के अंत में 322.2 बिलियन अमरीकी डालर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष में विदेशी मुद्रा भंडार 286.0 बिलियन अमरीकी डालर और 295.6 बिलियन अमरीकी डालर के बीच बना रहा है। दिसंबर अंत 2012 में यह भंडार 295.6 बिलियन अमरीकी डालर पर उठा हुआ था जो मार्चान्त 2012 में 294.4 बिलियन अमरीकी डालर से 1.2 बिलियन अमरीकी डालर की मामूली वृद्धि को इंगित करता है। रुपया 27 जून 2012 को 57.22 रुपए प्रति अमरीकी डालर पर सर्वकालिक निम्न था जिसने 30 मार्च 2012 को 51.16 रुपए प्रति अमरीकी डालर की तुलना में 10.6 प्रतिशत का मुल्यह्रास दर्शाया है। रुपए का मूल्य 5 अक्टूबर 2012 को बढ़कर 51.62 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया। हालांकि, तत्पश्चात इसने फिर गिरना शुरू कर दिया और तब से अक्टूबर से दिसंबर 2012 के बीच रुपए की मासिक विनिमय औसत दर 53.02 रुपए से 54.78 रुपए के बीच है।

माह-दर-माह आधार पर रुपया मार्च 2012 में 50.32 रुपए प्रति अमरीकी डालर से 7.9 प्रतिशत से गिरकर दिसंबर 2012 में 54.65 रुपए प्रति अमरीकी डालर हो गया। इसी तरह रुपये की मासिक औसत विनिमय दर मार्च 2012 और दिसंबर 2012 के बीच पौंड स्टर्लिंग के प्रति 9.7 प्रतिशत, यूरो के प्रति 7.2 प्रतिशत और जापाना येन के पश्चात 6 प्रतिशत मूल्यह्रास हुआ। भारत का विदेशी ऋण स्टाक मार्चान्त 2012 के स्तर की तुलना में लगभग 20.0 बिलियन अमरीकी डालर (5.8 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए सितंबर अंत में 2012 में 365.3 बिलियन अमरीकी डालर पर था। यह वृद्धि मुख्यतया उच्च एनआरआई जमाराशियों, अल्पावधिक ऋण और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के कारण थी।

### मुद्रा, बैंकिंग और पूंजी बाजार

जनवरी, 2010 से अक्टूबर 2011 के दौरान बढ़ते हुए स्फीतिकारी दबावों से भारतीय रिजर्व बैंक को कठोर मौद्रिक नीति अपनाने की जरूरत पड़ी। इस अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरें (रेपो दरें) 4.75 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत करके 375 आधार बिंदु की बढ़ोतरी की। मुद्रास्फीति अप्रैल 2010 में 10.9 प्रतिशत के शीर्ष से मंद होकर अप्रैल-दिसंबर, 2012 के दौरान औसतन 7.6 प्रतिशत हो गई थी। तथापि, बाह्य के साथ-साथ घरेलू स्रोतों से वृद्धि के बढ़ते हुए जोखिम और निरंतर स्फीतिकारी दबावों के आलोक में कठोर मौद्रिक नीति के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मंदी रही। अक्टूबर 2011 से भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत अवस्थिति में बदलाव हुआ है जिसमें इसने अंशशोधित तरीके से वृद्धि और मुद्रास्फीति की गतिशीलता के बीच संतुलना बैठाने का प्रयास किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी की स्थितियां सुधारने के लिए अप्रैल 2012 में रेपो दरें 50 आधार बिंदु व पुनः

जनवरी 2013 में 25 आधार बिंदु घटाई और नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) व सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) कम किया।

मौद्रिक कुलराशि की हलचल यह इंगित करती है कि व्यापक धन और ऋण की वृद्धि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित संकेतात्मक स्तरों से कम रही है। 2012-13 के दौरान, आरक्षित धन (एमओ) में वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत (25 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार) रही है, जबकि एम3 में वृद्धि 10.2 प्रतिशत (11 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार) रही। वर्षानुवर्ष, गैर खाद्य ऋण वृद्धि 15.7 प्रतिशत (11 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार) थी। केन्द्र के नकद शेषों में संचय, मुद्रा मांग में पर्व संबधित काफी वृद्धि, जमावृद्धि और ऋण वृद्धि के बीच बढ़ते अंतर द्वारा हुए संरचनात्मक दबावों के कारण नवम्बर के दूसरे सप्ताह से नकदी की शर्तें सख्त हुई हैं। नकदी के दबावों को महसूस करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) कम कर दिया है और खुली बाजार संक्रियाएं संचालित की हैं। इन उपायों के बावजूद, प्रणाली में नकदी घाटा भारतीय रिजर्व बैंक के सुविधास्तर से ऊपर रहा है।

वर्ष 2012 के दौरान देश में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के अंतर्वाहों को वर्धित होने से भारतीय बाजारों को वर्ष 2012 में विश्व में सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले बाजारों में बनने में सहायता मिली है और 2011 में निम्न निष्पादन से जल्दी से बाहर आने में सुधार हुआ है। 2012 में भारत में कुल निवल एफआईआई अंतर्वाह 31.01 रहा है। ये बिलियन प्रवाह मुख्य रूप से उन उक्विटी अंतर्वाहों (कुल प्रवाहों का 80 प्रतिशत) द्वारा चालित थे जो सामान्य रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के तथा विशेषरूप में भारतीय बाजारों के निष्पादन में ऐसे निवेशकों का विश्वास दर्शाते हुए अल्पावक रहे हैं। यूरो क्षेत्र तथा संयुक्त राज्य में आर्थिक और राजनैतिक घटनाक्रमों ने भारत सहित विश्व के बाजारों में अपना प्रभाव डाला था। अमरीका में “राजकोषीय व्यवधान” के अस्थायी रूप से समाधान होने से भारत सहित विश्वव्यापी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके आलावा, फिलहाल सरकार द्वारा किए गए सुधार संबधी उपायों से बाजारों में काफी लाभ हुआ है।

### केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति

2010-11 में केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत कम हुआ है और इसके बाद वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पुनरुज्जीवन हुआ और राजकोषीय तेजी में आंशिक कमी आई जो 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के तत्काल बाद स्थापित हुई थी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से कमी, विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में, ने मुद्रास्फीति के स्तरों को उठा दिया और वित्तीय बाजारों को मंदा कर दिया और उच्च वैश्विक कच्चे तेल और उर्वरकों के मूल्यों के बने रहने से 2011-12 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत

अधिक हो गया (अंतिम वास्तविक आंकड़े)। 2011-12 में राजकोषीय घाटे के बजट वाले स्तर में गिरावट 1.1 प्रतिशत थी। लगभग 35 प्रतिशत कमी राजस्व प्राप्तियों की बजटीय व्यवस्था की तुलना में कमी के कारण, 23 प्रतिशत की कमी विनिवेश की बजटीय व्यवस्था तथा ऋणों की वसूली में कमी के कारण तथा शेष मुख्यतः पेट्रोलियम और उर्वरकों के कारण उच्च सब्सिडी व्यय से उत्पन्न बजटीय व्यवस्था में व्यय की तुलना में अधिकता के कारण थी। पेट्रोलियम उत्पादों तथा उर्वरकों के मूल्यों में अपर्याप्त संशोधन 2011-12 में राजकोषीय परिणाम में प्रमुख कारण था।

2011-12 के प्रतिकूल वृहत-आर्थिक घटनाक्रम चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में चलते रहे। यह 2012-13 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में व्यापक आधार पर कमी के संदर्भ में व्यक्त हुआ था जो सीएसओ के अग्रिम अनुमानों द्वारा 5.0 प्रतिशत पर स्थापित है, मुख्य मध्यवर्तियों तथा मुद्रास्फीति के वैश्विक मूल्यों के अभी तक वर्धित स्तर 7 प्रतिशत से ज्यादा बने रहे यद्यपि 2011-12 की तुलना में कमी हुई है। सरकार ने मध्यावधि संशोधनों के भाग के रूप में सुधारों हेतु ठोस प्रयास किए। केलकर समिति की स्थापना प्रारंभिक कदम था। इसकी सिफारिश का पालन करते हुए, सरकार ने संशोधित राजकोषीय समेकन रोडमैप उद्घाटित किया तथा डीजल की कीमतों में संशोधन, विनिवेश प्रक्रिया को तेज करना आदि जैसे बहुत से उपाय किए। मध्यवर्षीय आर्थिक विश्लेषण 2012-13 ने चालू राजकोषीय वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की राजकोषीय घाटे में कमी इंगित की थी जो राजकोषीय वर्ष के पूर्वार्ध में वृहत आर्थिक परिणाम का संकेत करती है। केन्द्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति के संबंध में अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के लिए महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बजट अनुमान 2012-13 में वर्षानुवर्ष अप्रत्यक्ष वृद्धि के स्तर की तुलना में गैर ऋण प्राप्तियों में वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में सकल कर राजस्व 6,81,345 करोड़ रुपए तक होने के लिए वर्षानुवर्ष 15 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि वृद्धि का यह स्तर अप्रैल-दिसम्बर, 2011 में वृद्धि के स्तर से 12.2 प्रतिशत से अधिक है, यह उस वृद्धि में महत्वपूर्ण कमी दर्शाता है जो बजट अनुमान 2012-13 में परिकल्पित की गई थी बजट अनुमान के अनुपात के रूप में अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में सकल कर राजस्व 63.2 प्रतिशत था, जो पिछले पाँच वर्षों के 69.0 प्रतिशत के औसत से कम था। अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में गैर कर राजस्व 86,380 करोड़ रुपए है जो बजट अनुमान का 52.5 प्रतिशत है और पिछले पाँच वर्षों की औसत से काफी कम है। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में, मुख्यरूप से विनिवेश के कारण अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में महत्वपूर्ण कमी हुई है, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए की बजटीय राशि का केवल 8,178 करोड़ रुपए प्राप्त किया गया है।

मध्यावधिक संशोधन के भाग के रूप में किए गए उपायों ने 2012-13 में व्यय परिणाम सुधारने में मदद की है। बजट अनुमान

2012-13 में परिकल्पित 14.8 प्रतिशत की अंतर्निहित वर्षानुवर्ष वृद्धि के मुकाबले (2011-12 के अन्तर्गत वास्तविक से ज्यादा) अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में कुल व्यय में वृद्धि केवल 10.6 प्रतिशत रही है। बजट अनुमान के अनुपात के रूप में अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय 72.3 प्रतिशत है जो 77.7 प्रतिशत की पाँच वर्ष की औसत से काफी कम है। इसी प्रकार अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में आयोजना राजस्व एवं आयोजना पूंजीगत व्यय दोनों में व्यय बजट अनुमान के अनुपातों के रूप में पाँच वर्ष के औसत से काफी कम है। तथापि, अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में मुख्य सब्सिडियाँ प्रदान की गईं ताकि 1,66,824 करोड़ रुपए (बजट अनुमान का 92.9 प्रतिशत की संख्या तक पहुँचा जा सके) व्यय प्रतिबंध ने अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में घाटों को कम रखने में सहायता की है। 2012-13 के लिए बजट ने 5,13,590 करोड़ रुपए के घाटे के स्तर का अनुमान लगाया है। गैर ऋण प्राप्तियों और व्यय प्रतिबंध में कमी के निवल परिणाम ने अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे के वांछित संकेत को संदर्भ में परिणाम को पोषित किया है। बजट अनुमान के अनुपात के रूप में, राजकोषीय घाटा 78.8 प्रतिशत रहा है। जो 85.9 प्रतिशत की पाँच वर्ष की औसत तथा पिछले वर्ष के 92.3 प्रतिशत के स्तर से काफी कम रहा है। अप्रैल-दिसम्बर, 2012 में उपरोक्त परिणाम तथा चौथी तिमाही के संभावित परिणाम के आधार पर, संशोधित अनुमानों में 2012-13 में राजकोषीय तथा राजस्व घाटा क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद का 5.2 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत रहा।

### संभावना

वर्ष 2012 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में धीमी गति से विकास होता रहा। वर्ष 2013 में विश्व की अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तथापि, उबरने की प्रक्रिया धीमी रहने तथा इसमें अनिश्चितता रहने की संभावना है। मुद्रास्फीति 2011-12 में अधिक रही इसकी तुलना में 2012-13 में कम हुई। तथापि, गिरावट की गति धीमी रही है, और नीतिगत दरों में पर्याप्त कटौती करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपेक्षित गुंजाइश नहीं रही। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2011-12 में 6.2 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 5.0 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है।

तथापि, अर्थव्यवस्था में निवेश विश्वास बढ़ाने तथा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार की आशा के साथ-साथ राजकोषीय स्थिति सुधारने के लिए हालिया सुधार उपायों से 2013-14 में विकास के पुनरुद्धार की संभावना है। वर्ष 2013-14 में समग्र वृद्धि दर 6.1 से 6.7 प्रतिशत के दायरे में रहने की संभावना है। निःसंदेह इन अनुमानों में परिकल्पना की गई है कि यदि मानसून सामान्य रहा तो मुद्रास्फीति की दर और कम होगी और प्रत्याशित वैश्विक विकास की मध्यम वापसी होगी।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण  
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2010-11	2011-12	2010-11	2011-12
<b>संपदा क्षेत्र</b>					
1.	उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)*				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	8353 <sup>1 सं.अ.</sup>	9462 <sup>अ.अ.</sup>	15.0 <sup>1 सं.अ.</sup>	13.3 <sup>अ.अ.</sup>
	(ख) 2004-2005 के मूल्यों पर	5244 <sup>1 सं.अ.</sup>	5503 <sup>अ.अ.</sup>	6.2 <sup>1 सं.अ.</sup>	5.0 <sup>अ.अ.</sup>
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2004-05=100)	167	168.2	3.7	0.7
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100) @	155.0	166.7	9.4	7.6
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: औद्योगिक कामगार (2001=100) @	193.3	212.9	8.8	10.0
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (हजार करोड़ रुपए)\$	7221	8032	16.0	11.2
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात**				
	(क) करोड़ रुपए	1714432	1967522	52.2	14.8
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	363838	361272	35.2	-0.7
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात **				
	(क) करोड़ रुपए	1066668	1166439	41.9	9.4
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	226551	214100	29.6	-5.5
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)**	137317	147172	45.5	7.2
9.	विदेशी मुद्रा भंडार				
	(क) बिलियन रुपए में	15804	16194	18.6	2.5
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर में	296.7	295.6	-0.2	-0.4
10.	चालू लेखा शेष (मिलियन अमरीकी डालर में) (अप्रैल-सितंबर)	-36433	-38973	19.1	7.0
<b>सरकारी वित्त साधन #</b>		<b>₹ crore</b>			
1.	राजस्व प्राप्तियां	498,491	570,536	-14.7	14.5
2.	कर राजस्व (निवल)	420414	484156	7.5	15.2
3.	कर-भिन्न राजस्व	78077	86380	-59.6	10.6
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	397,870	420,587	96.4	5.7
5.	ऋणों की वसूली	14115	7710	64.3	-45.4
6.	अन्य प्राप्तियां	2743	8178	-87.9	198.1
7.	उधार और अन्य देनदारियां	381012	404699	122.5	6.2
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	896,361	991,123	13.9	10.6
9.	आयोजना-भिन्न व्यय	619,457	695,233	15.4	12.2
10.	राजस्व खाता	550692	625598	12.9	13.6
<i>जिसमें:</i>					
11.	ब्याज भुगतान	179429	201959	22.6	12.6
12.	पूंजी खाता	68765	69635	39.7	1.3
13.	आयोजना व्यय	276904	295890	10.8	6.9
<i>जिसमें:</i>					
14.	राजस्व खाता	233903	242975	9.9	3.9
15.	पूंजी खाता	43001	52915	16.0	23.1
16.	कुल व्यय (9+13)	896,361	991,123	13.9	10.6
17.	राजस्व व्यय (10+14)	784,595	868,573	12.0	10.7
18.	पूंजी व्यय (12+15)	111,766	122,550	29.5	9.6
19.	राजस्व घाटा (17-1)	286,104	298,037	146.0	4.2
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	381,012	404,699	122.5	6.2
21.	प्राथमिक घाटा (20-11)	201,583	202,740	708.1	0.6

त्व.अ. त्वरित अनुमान;

अ.अ. अग्रिम अनुमान

\* पूर्ण वर्ष से संबंधित

@ अप्रैल से दिसम्बर की औसत

\$ एम<sub>3</sub> संबंधी आंकड़े वर्ष 2011-12 के लिए 30 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार और 2012-13 के लिए 28 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार दिए गए हैं।

\*\* सीमाशुल्क आधार पर; चालू वर्ष हेतु संशोधित आधार की तुलना में अनन्तिम आधार पर।

# लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े।